

दलबदल वरिधी कानून

प्रलिमिंस के लिये:

दलबदल वरिधी कानून, दसवीं अनुसूची, संसद, संवैधानिक संशोधन।

मेन्स के लिये:

भारतीय संविधान, संवैधानिक संशोधन, दलबदल वरिधी कानून और संबंधित मुद्दे, दसवीं अनुसूची, न्यायिक समीक्षा, सूचना का अधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में मौजूद **दलबदल वरिधी कानून** में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिये इसमें संशोधन करने का समय आ गया है।

दलबदल वरिधी कानून:

- दल-बदल वरिधी कानून **संसद/विधानसभा** सदस्यों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने पर दंडित करता है।
- संसद ने इसे **1985 में दसवीं अनुसूची** के रूप में संविधान में जोड़ा। इसका उद्देश्य दल बदलने वाले वधायकों को हतोत्साहित कर सरकारों में स्थिरता लाना था।
 - **दसवीं अनुसूची** जिससे दलबदल वरिधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, को **52वें संशोधन अधिनियम, 1985** के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था और यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दलबदल के आधार पर नरिवाचति सदस्यों की अयोग्यता के लिये प्रावधान नरिधारति करता है।
- हालाँकि यह **सांसद/वधायकों** के एक समूह को दलबदल के लिये **दंड के बिना किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने (अर्थात् वलिय)** की अनुमति देता है। इस प्रकार यह दलबदल करने वाले वधायकों को प्रोत्साहित करने या स्वीकार करने के लिये राजनीतिक दलों को दंडित नहीं करता है।
 - 1985 के अधिनियम के अनुसार, एक **राजनीतिक दल के नरिवाचति सदस्यों के एक-तर्हिाई सदस्यों द्वारा 'दलबदल' को 'वलिय' माना जाता था।**
 - 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के अनुसार, दलबदल वरिधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ वलिय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उसके **कम-से-कम दो-तर्हिाई सदस्य वलिय** के पक्ष में हों।
- इस प्रकार इस कानून के तहत एक बार अयोग्य सदस्य उसी सदन की किसी सीट पर किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ सकते हैं।
- दलबदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर नरिणय के लिये मामले को सदन के सभापति या अध्यक्ष के पास भेजा जाता है, जो **कनियायकि समीक्षा** के अधीन होता है।
 - हालाँकि कानून एक समय-सीमा प्रदान नहीं करता है जिसके भीतर **पीठासीन अधिकारी को दलबदल** के मामले का फैसला करना होता है।

अयोग्यता का आधार:

- यदि एक **नरिवाचति सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल** की सदस्यता को छोड़ देता है।
- यदि वह पूर्व **अनुमति प्राप्त किये बिना अपने राजनीतिक दल या ऐसा करने के लिये** अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी किसी भी नरिदेश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है।
 - उसकी अयोग्यता के लिये पूर्व शर्त के रूप में ऐसी घटना के 15 दिनों के भीतर उसकी पार्टी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा मतदान से मना नहीं किया जाना चाहिये।
- यदि कोई नरिदलीय नरिवाचति सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- यदि छह महीने की समाप्त के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

दलबदल वरिधी कानून से संबंधित मुद्दे:

- **प्रतनिधि और संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करना:**
 - दलबदल वरिधी कानून के लागू होने के पश्चात् सांसद या वधायक को पार्टी के नरिदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होता है ।
 - यह उन्हें कसि भी मुददे पर अपने नरिणय के अनुरूप वोट देने की स्वतंत्रता नहीं देता है जससे प्रतनिधि लोकतंत्र कमजोर होता है ।
- **अध्यकष की वविदास्पद भूमिका:**
 - दल-बदल वरिधी मामलों में सदन के अध्यक्ष या स्पीकर की कार्रवाई की समय सीमा से संबंधति कानून में कोई स्पष्टता नहीं है ।
 - कुछ मामलों में **छह महीने** और कुछ में **तीन वर्ष** भी लग जाते हैं । कुछ ऐसे मामले भी हैं जो अवधिसमाप्त होने के बाद नपिटाए जाते हैं ।
- **वभिजन की कोई मान्यता नहीं:**
 - 91वें संवैधानिक संशोधन 2004 के कारण दलबदल वरिधी कानून ने दलबदल वरिधी शासन को एक अपवाद बनाया ।
 - हालाँकि यह संशोधन कसि पार्टी में 'वभिजन' को मान्यता नहीं देता है बल्कि इसके बजाय 'वलिय' को मान्यता देता है ।
- **चुनावी जनादेश का उल्लंघन:**
 - दलबदल उन वधायकों द्वारा चुनावी जनादेश का अपमान है जो एक पार्टी के टिकट पर चुने जाते हैं, लेकिन **फरि मंत्री पद या वत्तीय लाभ के लालच के चलते दूसरे में स्थानांतरति होना सुवधिजनक समझते हैं ।**
- **सरकार के सामान्य कामकाज पर प्रभाव:**
 - 1960 के दशक में वधायकों द्वारा लगातार दलबदल की पृष्ठभूमि के खलिफ कुख्यात "**आया राम, गया राम**" का नारा गढ़ा गया था । दलबदल के कारण सरकार में अस्थरिता पैदा होती है और प्रशासन प्रभावति होता है ।
- **हॉर्स-ट्रेडिंग को बढ़ावा:**
 - दलबदल वधायकों के खरीद-फरोख्त को भी बढ़ावा देता है जो स्पष्ट रूप से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के जनादेश के खलिफ माना जाता है ।
- **केवल थोक दलबदल की अनुमति:**
 - यह थोक दलबदल (एक साथ कई सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन) की अनुमति देता है लेकिन **खुदरा दलबदल (बारी-बारी से या एक-एक करके सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन) की अनुमति नहीं** देता । अतः इसमें नहिति खामियों को दूर करने के लिये संशोधन की आवश्यकता है ।
 - उन्होंने चति जताई कयिद कोई राजनेता कसि पार्टी को छोड़ता है, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन उस अवधि के दौरान **से नई पार्टी में कोई पद नहीं दिया जाना चाहिये ।**

सुझाव:

- **चुनाव आयोग** ने सुझाव दिया है कि दलबदल के मामलों में इसके लिये नरिणायक प्राधिकारी होना चाहिये ।
- दूसरों ने तर्क दिया है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को दलबदल याचिकाओं पर सुनवाई करनी चाहिये ।
- **सर्वोच्च न्यायालय** ने सुझाव दिया है कि संसद को उच्च न्यायापालिका के एक सेवानवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र न्यायाधिकरण का गठन करना चाहिये ताकि दलबदल के मामलों का तेज़ी और नषिपकष रूप से फैसला कया जा सके ।
- कुछ टपिपणीकारों ने कहा है कि यह कानून वफिल हो गया है और इसे हटाने की सफारिश की है । पूर्व उपराष्ट्रपति हामदि अंसारी ने सुझाव दिया है कि यह केवल **अवशिवास प्रस्ताव** के मामले में सरकारों को बचाने के लिये लागू होता है ।

आगे की राह

- मूल समस्या की उत्पत्ति अनविर्य रूप से कसि राजनीतिक समस्या का कानूनी समाधान खोजने के प्रयास में नहिति है ।
- यदि सरकार की अस्थरिता का कारण दलबदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराया जाना है तो इसके लिये इन दलों के आंतरिक लोकतंत्र को मज़बूत करना होगा ताकि पार्टी वखिंडन की घटनाओं को रोका जा सके ।
- भारत में राजनीतिक दलों को नर्यितरति करने वाले कानून की अत्यंत आवश्यकता है । इस तरह के कानून में राजनीतिक दलों को **सूचना का अधिकार (RTI)** के दायरे में लाया जाना चाहिये, साथ ही पार्टी के भीतर लोकतंत्र को मज़बूत करना चाहिये ।
- प्रतनिधि लोकतंत्र में **दल-बदल वरिधी कानून के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिये, कानून के वसितार को केवल उन कानूनों तक सीमति कया जा सकता है, जहाँ सरकार की हार से वशिवास समाप्त हो सकता है ।**

UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. भारत के संवधान की नमिनलखिति में से कौन-सी एक अनुसूची में दलबदल वरिधी कानून संबंधी उपबंध है?

- दूसरी अनुसूची
- पाँचवी अनुसूची
- आठवी अनुसूची
- दसवी अनुसूची

उत्तर: (d)

स्रोत: द हट्टु

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/anti-defection-law-5>

